Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कमार जनजातियों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका : छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास परिप्रेक्ष्य में एक केस अध्ययन

कृति वर्मा* आशिष कुमार डॉ. एल.एस. गजपाल*****

* शोधार्थी, क्षेत्रीय अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
*** प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कमार जनजातियों में आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका कैसे परस्पर क्रिया करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सरकारी पहल, एनजीओ कार्यक्रम और समुदाय-आधारित परियोजनाओं सहित ग्रामीण विकास गतिविधियां, कमार लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं। केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, पेपर पारंपरिक आजीविका रणनीति, कमाई पैदा करने वाली गतिविधियों में बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उपयोग तक पहुंच और स्थानीय शासन संस्थानों में भागीदारी की जांच करता है। प्राथमिक डेटा धमतरी और गरियाबंद जिलों के चुने हुए गांवों में हुए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों और फोकस समूह चर्चाओं का उपयोग करके एकत्र किया गया था। निष्कर्षों से पता चलता है कि हालांकि कुछ विकास प्रयासों के अनुभव से बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है और आजीविका की संभावनाएं बढ़ी हैं, भूमि विस्थापन, जागरूकता की कमी और सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां स्थायी आर्थिक प्रगति में बाधा बनी हुई हैं। लेख समग्र, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भागीदारीपूर्ण ग्रामीण विकास नीतियों को बढ़ावा देने के साथ समाप्त होता है जो दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कमार जनजातियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करता है।

शब्द कुंजी –आर्थिक सशक्तिकरण, सतत आजीविका, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, आजीविका विविधीकरण, पारंपरिक प्रथाएं, स्वदेशी समुदाय।

प्रस्तावना – कमार जनजाति भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मध्य-पूर्वी जिलों, जैसे गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी में रहते हैं। जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा किए गए जनजातीय अध्ययनों और क्षेत्र सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार, कमार एक वन-निर्भर जनजातीय समुदाय है, जिसकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था स्थानांतरित खेती, वन उपज संग्रह, मछली पकड़ने और मजदूरी पर आधारित है। उनकी आबादी अपेक्षाकृत कम है, अनुमानित रूप से लगभग 35,000 (जनगणना 2011 और राज्य-स्तरीय टीआरटीआई डेटा), और वे मुख्य रूप से कमार बोली बोलते हैं, जो स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा का एक रूप है। जनजाति पितृसत्तात्मक और अंतर्विवाही है, हिंदू रीति-रिवाजों के साथ-साथ जीववादी मान्यताओं का पालन करती है और स्थानीय देवताओं और प्रकृति आत्माओं की पूजा करती है। सामाजिक-आर्थिक रूप से, कमार को कम साक्षरता दर, उच्च गरीबी स्तर, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक खराब पहुंच और भूमि हस्तांतरण सहित कई कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य ने पीवीटीजी विकास कार्यक्रम के तहत विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनमें आवास, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य आउटरीच तक पहुंच शामिल है। इन प्रयासों के बावजूद, टीआरटीआई रिपोर्टें कमार जनजाति के सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अधिक समावेशी और समुदाय-विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालती रहती हैं।

परंपरागत रूप से, कमार जनजाति वन-आधारित आजीविका पर निर्भर रही है, जिसमें लघु वन उत्पादों का संग्रह, शिकार और निर्वाह कृषि शामिल है। हालाँकि, तेजी से हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों, वनों की कटाई और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण, उनकी पारंपरिक जीवनशैली तेजी से खतरे में है। इस परिदृश्य में, ग्रामीण विकास पहल उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आर्थिक सशक्तिकरण को व्यक्तियों या समुदायों की सूचित विकल्प बनाने और उन विकल्पों को वांछित कार्यों और परिणामों में बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से आय-सृजन के अवसरों, शिक्षा और संपत्तियों तक पहुंच के माध्यम से। इसके विपरीत, टिकाऊ आजीविका उन तरीकों से जीवन को सुरक्षित करने की क्षमता को संदर्भित करती है जो दीर्घकालिक रूप से पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य, आर्थिक रूप से प्रभावी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत हों।

इस शोध का उद्देश्य कमार जनजातियों के लिए ग्रामीण विकास के ढांचे के भीतर दो अवधारणाओं–आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका–के अभिसरण की जांच करना है। यह कमार आबादी के आर्थिक मार्गों पर विभिन्न सरकारी पहलों, एनजीओ गतिविधियों और समुदाय–संचालित प्रयासों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी और गरियाबंद जिलों के विशिष्ट गांवों पर ध्यान केंद्रित करके, यह अध्ययन आदिवासी विकास में वास्तविक दुनिया की स्थितियों, बाधाओं और संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए एक केस स्टडी पद्धति का उपयोग करता है। प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक, समावेशी और भागीदारीपूर्ण विकास रणनीतियों की आवश्यकता तेजी से जरूरी हो गई है, खासकर कमार जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए। प्रभावी और टिकाऊ ग्रामीण विकास नीतियों को विकसित करने के लिए उनकी वर्तमान आजीविका प्रथाओं, आर्थिक भागीदारी की चुनौतियों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक कृषि फसल उत्पादन प्रणाली तकनीकी प्रगति, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और आबादी की बढ़ती जरूरतों और मांगों के कारण क्रमिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत वैश्विक खाद्य उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनाज, बाजरा, सब्जियों की खेती और पशुपालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में आदिवासी किसानों की भागीदारी इस वैश्विक उत्पादन ढांचे का अभिन्न अंग है। आदिवासी शब्द इन आदिवासी समुदायों को संदर्भित करता है, जिसका अनुवाद स्वदेशी लोग होता है। भारत में, जनजातीय आबादी कुल आबादी का लगभग 8.9 प्रतिशत है और मुख्य रूप से पूरे देश में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है (जनसंख्या जनगणना 2011)। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (कुंभकर, 2010) में केंद्रित हैं। आदिवासी किसान कृषि पद्धतियों से गहराई से जुड़े हुए हैं जो अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। वे आम तौर पर अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में विविध कृषि प्रणालियों में संलग्न होते हैं। हालाँकि, हाल की कृषि तकनीकी प्रगति के बारे में उनकी समझ उनके गैर–आदिवासी समकक्षों (दास और साहू, 2012) की तुलना में सीमित है। आदिवासी कृषि प्रणाली को बढ़ाने और आजीविका में सुधार के लिए विभिन्न सरकारी विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं।

साहित्य समीक्षा

गुप्ता, ए.के., और शर्मा, एम.एल. (2017), द्वारा इस अध्ययन में 135 बेतरतीब ढंग से चयनित उत्तरदाताओं के साथ पूर्व–पोस्ट डिजाइन का उपयोग करके बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (2014–2015) में जनजातियों की स्थायी आजीविका प्रणालियों की जांच की गई। छह आजीविका राजधानियों के विश्लेषण से कुल आजीविका स्थिति 40.17% दिखाई गई, जिसमें मानव और सामाजिक पूंजी में मध्यम स्तर और अन्य में निम्न स्तर था। पंद्रह में से तेरह चर ने आजीविका सीमा के साथ महत्वपूर्ण सहसंबंध दिखाया, और प्रतिगमन विश्लेषण ने 66.4% भिन्नता का संकेत दिया। अध्ययन प्रभावी आदिवासी विकास योजना के लिए सभी छह राजधानियों, विशेष रूप से भौतिक, प्राकृतिक, वित्तीय और सूचना संचार में केंद्रित सुधार की सिफारिश करता है।

कुमार, (2025) आईसीएआर–अटारी जोन और सहयोगियों द्वारा आयोजित इस अध्ययन में 2016 से 2021 तक आदिवासी किसानों की आजीविका पर प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन किया गया। परिणामों ने फसल पैटर्न में सुधार, फसल तीव्रता में वृद्धि और गोद लिए गए गांवों में विविध कृषि प्रणालियों की ओर बदलाव दिखाया। क्ष37,587.16 हेक्टेयरवर्ष के शुद्ध लाभ और उच्च लाभ–लागत अनुपात (2.04 बनाम 1.2) के साथ, इन क्षेत्रों में आय का स्तर काफी बढ़ गया। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों ने जनजातीय आजीविका में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है, हालांकि विपणन और आर्थिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

सरावगी, ए., और सिंह, एम. (2024) का यह अध्ययन सोनभद्र में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में एसएचजी की भूमिका का मूल्यांकन करता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि एसएचजी आजीविका में मामूली वृद्धि करते हैं, जिससे आय, बचत और रोजगार में महत्वपूर्ण सुधार होता है। एसएचजी भागीदारी दृढ़ता से सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण की भविष्यवाणी करती है, जिसमें लाभार्थियों के पास सकारात्मक धारणाएं हैं। एसएचजी पहलों के निरंतर समर्थन और विस्तार की सिफारिश की जाती है।

शर्मा, (2014). इस अध्ययन में 80 सदस्यों के बीच आजीविका सुरक्षा और लिंग सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव का आकलन किया गया। निष्कर्षों से पता चलता है कि एसएचजी, विशेष रूप से सफल एसएचजी, ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा, आत्मविश्वास और समग्र सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। समूह की भागीदारी ने सदस्यों की जीवन चुनौतियों का प्रबंधन करने की क्षमता में काफी सुधार किया, जिससे जमीनी स्तर के विकास में एसएचजी की भूमिका पर प्रकाश पड़ा।

बेचेंज, (2021) ग्रामीण युगांडा में इस अध्ययन में पाया गया कि आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकलांग युवाओं ने 12 महीनों के बाद रोजगार, वित्तीय पहुंच और सामुदायिक समर्थन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। हालाँकि, खाद्य सुरक्षा और भेदभाव का स्तर अपरिवर्तित रहा, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ–साथ व्यापक समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सिंधी, एस. (2012)यह अध्ययन कृषि वानिकी, सिलाई और सैनिटरी पैड बनाने जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरात में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों और सरकारी प्रयासों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सामाजिक बाधाओं और घरेलू चुनौतियों के बावजूद, कई महिलाओं ने कौशल विकास में भाग लेकर और स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आजीविका और स्वायत्तता में सफलतापूर्वक सुधार किया।

दत्ता, एस., और साहू, टी.एन. (202पांच पिछड़े भारतीय जिलों के 425 उत्तरदाताओं के इस अध्ययन से पता चलता है कि माइक्रोक्रेडिट आदिवासी समुदायों की आजीविका और सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप बदल देता है, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक भलाई में सुधार होता है। यह आदिवासी विकास के समर्थन में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर मूल्यांकन का आह्वान करता है।

जनजातीय संदर्भों में आर्थिक सशक्तिकरण

जाक्सा (2008), भारत में आदिवासी समुदाय ऐतिहासिक उपेक्षा और

मुख्यधारा की आर्थिक प्रक्रियाओं से बहिष्कार के कारण प्रणालीगत हाशिए पर हैं। कमार जनजाति जैसे पीवीटीजी के लिए, सशक्तिकरण को आय सृजन से परे जाना चाहिए और इसमें एजेंसियों, निर्णय लेने की शक्ति और संस्थागत समर्थन तक पहुंच शामिल होनी चाहिए।

सतत आजीविका ढांचा

डीएफआईडी, (1999) विभिन्न संपत्तियों – मानवीय, प्राकृतिक, वित्तीय, सामाजिक और भौतिक – को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण प्रदान करता है जो टिकाऊ जीवन में योगदान करते हैं।

स्कून्स (1998) का तर्क है कि स्थायी आजीविका लचीली, अनुकूली और पर्यावरणीय गिरावट, बाजार विफलताओं और विस्थापन जैसे झटकों से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जनजातीय आबादी के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता आर्थिक अस्तित्व से अविभाज्य है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय आजीविका

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (2022) का कहना है कि मनरेगा पीडीएस और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) जैसी सरकारी योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच गई हैं, कार्यान्वयन अंतराल और जागरूकता की कमी अक्सर उनके प्रभाव को सीमित कर देती है।

मिश्रा (2016) से पता चलता है कि विकास के लिए ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण अक्सर आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में विफल रहता है, जिससे अस्थिर परिणाम सामने आते हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

योजना आयोग की रिपोर्ट (2014) पीवीटीजी अत्यधिक गरीबी, स्वास्थ्य कमजोरियों और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। वनों की कटाई, पहुंच अधिकारों की हानि और बाजार शोषण के कारण उनकी पारंपरिक वन–आधारित आजीविका खतरे में है।

शर्मा और सिन्हा (2019) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पीवीटीजी के लिए हस्तक्षेप समुदाय–संचालित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, जिसमें विकास योजना में स्थानीय ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्यक्रमों को साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जमीनी स्तर पर संस्थान निर्माण सहित क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

साहित्य में अंतराल – सामान्य तौर पर जनजातीय विकास पर पर्याप्त साहित्य मौजूद है, विशेष रूप से कमार जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुभवजन्य अध्ययन सीमित हैं। ग्रामीण विकास पहलों ने कमार के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका स्थिरता को कैसे प्रभावित किया है, इसकी खोज करने वाले जमीनी स्तर, भागीदारी अनुसंधान की उल्लेखनीय कमी है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के नमूना गांवों में कमार समुदाय के जीवन के अनुभवों पर आधारित केस स्टडी दृष्टिकोण को अपनाकर उस अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कमार जनजातियों की पारंपरिक और वर्तमान आजीविका प्रथाओं की जांच करना।
2. कमार आदिवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।
3. स्थायी आजीविका प्राप्त करने में कमार जनजातियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।
4. कमार जनजातियों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय–आधारित संगठनों की भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन का दायरा – यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से धमतरी और गरियाबंद जिलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कमार जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका पर केंद्रित है। शोध कमार समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर सरकारी योजनाओं, एनजीओ के हस्तक्षेप और सामुदायिक प्रयासों सहित विभिन्न ग्रामीण विकास पहलों के प्रभाव की जांच करता है।

अध्ययन में शामिल – पारंपरिक आजीविका पैटर्न और समय के साथ परिवर्तन , सरकारी कल्याण कार्यक्रमों और ग्रामीण विकास योजनाओं तक पहुंच और प्रभावशीलता , भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाजार पहुंच से संबंधित चुनौतियाँ , आर्थिक गतिविधियों और निर्णय लेने में महिलाओं और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका , पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के संदर्भ में आजीविका प्रथाओं की स्थिरताहालाँकि, अध्ययन भौगोलिक रूप से चयनित गाँवों तक ही सीमित है जहाँ कमार जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है और इसमें छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी समूह या शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं। अनुसंधान मुख्य रूप से सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों से प्राप्त कुछ मात्रात्मक डेटा द्वारा पूरक गुणात्मक तरीकों का उपयोग करता है।

अध्ययन क्षेत्र – छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मगरलोड विकास खंड, कमार जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श केंद्र क्षेत्र प्रस्तुत करता है। अगस्त 2023 में, यह ब्लॉक एक अग्रणी स्थल बन गया जहां 22 कमार बस्तियों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण नीति मील का पत्थर है। इस प्रक्रिया में ग्राम सभाओं और पारंपरिक नेताओं सहित व्यापक सामुदायिक और संस्थागत भागीदारी शामिल थी, जो स्थानीय शासन और क्षमता निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती थी। जबकि कमार जनजाति गरियाबंद, महासमुंद और कांकेर जिलों में भी फैली हुई है, मगरलोड निवास स्थान–आधारित आदिवासी विकास पहल के लिए एक पायलट के रूप में अपनी भूमिका के कारण सबसे अलग है। व्यापक समझ हासिल करने के लिए, नगरी (धमतरी), मैनपुर और छुरा (गरियाबंद), और बागबाहरा (महासमुंद) जैसे पड़ोसी ब्लॉकों में तुलनात्मक अध्ययन की सिफारिश की जाती है। यह दृष्टिकोण व्यापक प्रासंगिक अंतर्दृष्टि के साथ गहन विश्लेषण को संतुलित करता है, जिससे मगरलोड को निकटवर्ती क्षेत्रों में तुलनात्मक जांच द्वारा पूरक प्राथमिक फोकस बनाया जाता है।

अनुसंधान पद्धति – यह अध्ययन ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कमार जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका का पता लगाने के लिए गुणात्मक केस अध्ययन दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह शोध धमतरी और गरियाबंद जिलों के चयनित गांवों पर केंद्रित है, जहां कमार समुदाय मुख्य रूप से निवास करता है। प्राथमिक डेटा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, अर्ध–संरचित साक्षात्कारों और समुदाय के सदस्यों, स्थानीय नेताओं और ग्रामीण विकास में शामिल सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ

फोकस समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किया जाता है। यह गुणात्मक डेटा व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए सरकारी रिपोर्टों, जनगणना डेटा, विद्वानों के लेखों और विकास एजेंसी प्रकाशनों से प्राप्त माध्यमिक डेटा द्वारा पूरक है। उपयोग की जाने वाली नमूनाकरण तकनीक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण है, जो उन परिवारों और व्यक्तियों को लक्षित करती है जो सीधे आजीविका गतिविधियों में लगे हुए हैं या ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थी हैं। डेटा विश्लेषण में आजीविका प्रथाओं, सशक्तिकरण स्तरों, चुनौतियों और विकास हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता से संबंधित पैटर्न की पहचान करने के लिए विषयगत कोडिंग शामिल है। यह मिश्रित दृष्टिकोण कमार जनजातियों के बीच आजीविका की स्थिरता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और प्रासंगिक कारकों दोनों की विस्तृत समझ को सक्षम बनाता है।

शोध सम्बन्धी सिफारिशें:

1. समावेशी, डेटा-सूचित शासन (उदाहरण के लिए, डिजिटल टूल एमआईएस के साथ सीआरपी) समुदायों को कल्याणकारी सेवाओं को समझने और उन तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है - जिससे अधिक प्रतिक्रियाशील और न्यायसंगत विकास होता है।
2. सुरक्षित आवास अधिकार सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता और कानूनी सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करते हैं, जिससे जनजातियों को विस्थापन के दबाव के बिना अपनी आजीविका को आकार देने में सक्षम बनाया जाता है।
3. आवास प्रावधान, विशेष रूप से मनरेगा जैसे मजदूरी कार्य घटकों के साथ, न केवल रहने की स्थिति में सुधार करता है, बल्कि वित्तीय स्वायत्तता और गरिमा भी चाहता है।
4. वन-आधारित अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैंरू वे कृषि या मजदूरी श्रम में उतार-चढ़ाव के बीच विविधता और लचीलापन दोनों प्रदान करते हैं।
5. इको-पर्यटन के अवसर, जैसा कि धुदमरास में देखा गया है, दिखाता है कि कैसे जलवायु- और संस्कृति-संवेदनशील विकास विरासत को संरक्षित करते हुए नई आय धाराएं प्रदान कर सकता है।

शोध सम्बन्धी चर्चा – छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड और नगरी ब्लॉक में केंद्रित कमार जनजाति एक अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह है, जिसकी आजीविका मुख्यत: वन उपज जैसे महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज और शहद पर तथा निर्वाह कृषि पर आधारित है। सीमित कृषि भूमि और सिंचाई संसाधनों के कारण खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर और एकल फसली होती है। कम साक्षरता दर, विशेष रूप से महिलाओं में उच्च ड्रॉपआउट की समस्या स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 70-80% परिवारों को कच्चे से पक्के मकानों का लाभ मिला है, वहीं मनरेगा, आयुष्मान, राशन और केसीसी कार्ड जैसी योजनाएं कुछ हद तक जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। 2023 में एफआरए (2006) के अंतर्गत 22 गांवों को कानूनी भूमि अधिकार और शासन में भागीदारी दी गई। बावजूद इसके, जागरूकता की कमी, नौकरशाही बाधाएं, बाजार में शोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी, और कुपोषण, मलेरिया जैसे रोगों की अधिकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। महिलाएं एनटीएफपी संग्रहण और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु एसएचजी, प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज तक सीमित पहुंच उनके सशक्तिकरण में बाधा बनी हुई है। फिर भी, इको-पर्यटन, वन आधारित उद्यम, और डिजिटल समावेशन के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर उभर रहे हैं, यदि इन्हें सही प्रशिक्षण और समर्थन मिले। नीति के स्तर पर आवश्यक है कि योजनाएं जन-केंद्रित, समग्र, विकेंद्रीकृत और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हों, ताकि कमार समुदाय का सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सकारात्मक प्रभाव

1. **आय में वृद्धि**-विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों जैसे लघु वनोपज संग्रह, कृषि आधारित उद्यम, और स्वरोजगार योजनाओं ने कमार समुदाय की पारिवारिक आय में वृद्धि की है, महिला स्व-सहायता समूहों के जरिए सूक्ष्म ऋण और बचत की सुविधा से भी आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है।
2. **आजीविका के वैकल्पिक स्रोत –**केवल वनोपज पर निर्भरता कम हुई है अब ये समुदायमुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन ,जैविक खेती ,हस्तशिल्पहथकरघा जैसे कार्यों से भी जुड़े हैं।
3. **महिला सशक्तिकरण**- महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय निर्णयों में भाग ले रही हैं ,कमार जनजाति की महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं।
4. **शिक्षा और जागरूकता में सुधार**- आर्थिक स्थिरता के साथ बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है , सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है (जैसे राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना आदि)।
5. **स्वास्थ्य व पोषण में सुधार –** नियमित आय और सरकार की योजनाओं से पोषण युक्त आहार की उपलब्धता बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा का उपयोग।
6. **कौशल विकास और प्रशिक्षण –** स्थानीय NGOsऔर सरकारी एजेंसियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण से कमार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं , ITI, PMKVआदि योजनाओं के तहत तकनीकी कौशल में वृद्धि हुई है।
7. **सामाजिक समावेश और आत्मसम्मान**- आर्थिक आत्मनिर्भरता से सामाजिक सम्मान बढ़ा है , ग्राम सभा, पंचायतों में भागीदारी बढ़ी है।
8. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल**-जब कमार समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो उनका उपभोग और लेन-देन गांव की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील करता है।

नकारात्मत प्रभाव

1. **पारंपरिक आजीविका और ज्ञान का ह्रास**- आधुनिक योजनाओं और प्रशिक्षणों के कारण कमारों की पारंपरिक आजीविका (जैसे - वनोपज संग्रह, पारंपरिक खेती) को छोड़ना पड़ रहा है, उनके पारंपरिक वन आधारित ज्ञान और जीवनशैली का क्षरण हो रहा है।
2. **पर्यावरणीय असंतुलन**- कुछ कृषि या पशुपालन योजनाएं स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं होतीं, जिससेरू जंगलों की कटाई बढ़ी , जल स्रोतों पर दबाव , जैव विविधता पर असर हुआ है।
3. **योजनाओं का अपर्याप्त क्रियान्वयन**- योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। भ्रष्टाचार, दलालों की भूमिका और अधिकारियों की उदासीनता के कारण लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचता।
4. **कर्ज के जाल में फँसना**- स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के नाम पर बैंक ऋण दिए जाते हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण और बाजार

व्यवस्था के अभाव में कई लोग व्यवसाय में असफल होकर कर्ज में डूब जाते हैं।

5. **आजीविका की अस्थिरता**– कई वैकल्पिक रोजगार टिकाऊ नहीं होते। जैसेरू एक सीजन के बाद मशरूम उत्पादन रुक जाता है, पशुपालन में बीमारियों से नुकसान होता है।

6. **सामाजिक विघटन**– आर्थिक असमानता बढ़ी हैरू कुछ लोग लाभ ले पाते हैं, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं , इससे आपसी तनाव, ईर्ष्या, और समाज में टूट का खतरा बढ़ता है।

7. **बाहरी हस्तक्षेप और शोषण**– जैसे ही समुदाय के पास थोड़ी आमदनी आती है, बाहरी व्यापारी, साहूकार और दलाल शोषण करने लगते हैं , उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

8. **प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी**– कई बार दिए गए प्रशिक्षण प्रासंगिक नहीं होते, प्रशिक्षण खत्म होने के बाद भी रोजगार का मार्ग नहीं खुलता।

9. **पलायन की प्रवृत्ति**– योजनाएं असफल होने पर कमार युवा शहरों की ओर पलायन करते हैं , इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में अस्थिरता आती है।

10. **सांस्कृतिक क्षरण**–आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में पश्चिमीकरण या शहरीकरण का प्रभाव बढ़ता है, जिससे पारंपरिक त्योहार, मान्यताएं और जीवन मूल्य खोते जा रहे हैं।

कार्यान्वयन – जनजातीय समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, लक्षित और समावेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से उनकी आर्थिक कमजोरियों से निपटना महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन शामिल है जो आय विविधीकरण पर जोर देते हैं और बाजार पहुंच बढ़ाते हैं, जिससे आदिवासी परिवारों को आजीविका के एक ही स्रोत पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं तक पहुंच को मजबूत करना – विशेष रूप से वे जो खेती, वन उपज संग्रह और पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों का समर्थन करते हैं – यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचें। समवर्ती रूप से, पारंपरिक आजीविका के भीतर टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए आवश्यक है। इसे प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण पहल की सुविधा प्रदान करके पूरा किया जा सकता है जो टिकाऊ कृषि, पर्यावरण–अनुकूल पशुपालन, वैज्ञानिक वन संसाधन प्रबंधन और मूल्य संवर्धन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करती हैं बल्कि आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष – अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण छत्तीसगढ़ की कमार जनजातियाँ वन–आधारित गतिविधियों और निर्वाह खेती जैसी पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के कारण विविध आय स्रोतों की ओर धीरे–धीरे बदलाव आया है। इन हस्तक्षेपों ने आंशिक आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान दिया है, विशेष रूप से रोजगार योजनाओं, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन के माध्यम से।हालाँकि, कमार जनजातियाँ अभी भी सीमित शिक्षा, खराब बाजार पहुंच, बुनियादी ढांचे की कमी और सामाजिक बहिष्कार सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती हैं, जो उनकी आजीविका की स्थिरता में बाधा डालती हैं। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और समुदाय–आधारित संगठनों ने समुदायों को एकजुट करने, कौशल निर्माण और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, उनके प्रयासों को व्यापक प्रभाव के लिए सरकारी कार्यक्रमों के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर, कमार जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका प्राप्त करने के लिए एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संस्थागत समर्थन को मजबूत करता है, क्षमता निर्माण में सुधार करता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है, और विकास के लिए प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करता है।कमार जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका ने उन्हें केवल जीविकोपार्जन ही नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक रूप से भी सशक्त किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को सकारात्मक दिशा मिली है। एवं कमार जनजाति के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका के प्रयासों से कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, लेकिन यदि इन्हें स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के बिना लागू किया गया तो ये प्रयास लाभ से अधिक नुकसान भी कर सकते हैं।

सुझाव:

1. पारंपरिक आजीविका को मजबूत करना।
2. सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच में सुधार।
3. प्रमुख विकास बाधाओं का समाधान करें।
4. गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों की भूमिका बढ़ाएँ।
5 सहभागी विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

छत्तीसगढ़ में कमार जनजातियों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ग्रामीण विकास रणनीति अपनाना आवश्यक है। वन उपज संग्रह और निर्वाह खेती जैसी पारंपरिक आजीविका प्रथाओं को मूल्य संवर्धन, बेहतर उपकरणों और बाजार पहुंच के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए, साथ ही कृषि–प्रसंस्करण, पर्यावरण–पर्यटन या स्थानीय कौशल के अनुरूप हस्तशिल्प जैसे वैकल्पिक आय–सृजन के अवसरों को भी पेश किया जाना चाहिए। समावेश सुनिश्चित करने के लिए लक्षित जागरूकता अभियानों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और नियमित निगरानी के माध्यम से सरकारी योजनाओं को कमार समुदाय के लिए अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। प्रणालीगत बाधाओं पर काबू पाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और वित्तीय साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय–आधारित संगठनों को कौशल विकास, वित्तीय पहुंच और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर सहभागी योजना और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने से विकास प्रयासों का स्वामित्व और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Kurrey, S. K., & Pradhan, A. (2014). Tribal Development: Problems and Possibilities (With Special Reference to Chhattisgarh PTG “Kamar”). IRJMSH,

5(8), 91–101.
2. Ministry of Tribal Affairs / UNDP (2023, August 9). Empowering Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs): Recognition of Habitat Rights in Chhattisgarh.
3. Vulnerable tribal group `Kamar' in Chhattisgarh's Dhamtari district gets habitat rights. The Indian Express, August 10, 2023.
4. Chhattisgarh's PVTG Kamar Tribe gets habitat rights on World Tribal Day. Times of India, August 10, 2023.
5. Dube, S./ C. (1951). The Kamar. Oxford University Press.
6. Mitra, M., Kumar, P./ V., Ghosh, R., & Bharati, P. (2002). Growth Pattern of the Kamars – A Primitive Tribe of Chhattisgarh, India. Collegium Antropologicum, 26(2), 485–499.
7. Nutritional Status of Kamar Tribal Children in Chhattisgarh. (Year unspecified). In Indian Pediatrics / Journal of Pediatric Nutrition series (PubMed entry).
8. Acharya, V., Sharma, V., Patra, P./ K., Naik, M./ L., & Kanungo, V./ K. (2012). Plants used by Kamar, Gond and Halba tribe of Dhamtari district of Chhattisgarh for relief of sickle cell disease. Recent Research in Science and Technology, 4(3).
9. Gupta, A. K., & Sharma, M. L. (2017). Sustainable Livelihood System of the Tribes in Chhattisgarh State of India: A Tribe's Perspective Analysis. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 16(4), 1–13. https://doi.org/10.9734/AJAEES/2017/31812
10. Sarawagi, A., & Singh, M. (2024). Enhancing livelihoods and empowering tribal women: Analyzing the role of self-help groups in Sonbhadra. Sachetas, 3(2), 23-30.
11. Anju, G. S., & Raju, J. K. (2014). Challenges of SHG's Rural Women Entrepreneurship with Special Reference to Davangere District. Global Journal of Commerce and Management Perspective, 3(5), 15-21.
12. Verma, A. K. (2013). Tribal `Annihilation' and `Upsurge' in Uttar Pradesh. Economic and Political Weekly 48(51), 52-59. https://www.jstor.org/stable/24478404 (retrieved on 08.03.2024).
13. Khan, M. I. (2015). Women empowerment, entrepreneurship, and capacity development. Journal for Studies in Management and Planning, 1(9), 43-56.
14. Mullen, J. (Ed.). (2019). Rural poverty, empowerment and sustainable livelihoods. Routledge.
15. Sharma, N., Wason, M., Singh, P., Padaria, R. N., Sangeetha, V., & Kumar, N. (2014). Effectiveness of SHGs in improving livelihood security and gender empowerment. Economic Affairs, 59, 747.
16. Bechange, S., Jolley, E., Gascoyne, B., Smith, K., Griffiths, A., Ngorok, J., & Schmidt, E. (2021). Livelihood outcomes in a cohort of youth with disabilities following participation in an economic empowerment programme in rural Uganda. Disability and Health Journal, 14(3), 101069.
17. Sindhi, S. (2012). Prospects and challenges in empowerment of tribal women. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 6(1), 46-54.
18. Datta, S., & Sahu, T. N. (2022). Livelihood transformation through microfinance: an empirical investigation on tribal entrepreneurs in India. International Journal of Business Innovation and Research, 29(1), 127-140.
19. DFID. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. Department for International Development. https://www.ennonline.net/dfidsustainableliving .
20. Ministry of Tribal Affairs. (2022). Report on Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India. Government of India.
21. Mishra, S. (2016). Livelihood strategies and forest dependence among tribes in Bastar, Chhattisgarh. Indian Journal of Rural Development, 35(2), 213–227.
22. Planning Commission. (2014). Report of the High-Level Committee on socio-economic, health and educational status of tribal communities of India. Government of India. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/reports/
23. Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/
24. Sharma, R., & Sinha, M. (2019). Development interventions and tribal resilience: A study of PVTGs in Central India. Social Change, 49(1), 35–50.
25. Xaxa, V. (2008). State, society, and tribes: Issues in post-colonial India. Pearson Education India.
26. Kumar, R., Kumar, B., Devi, M. T., Azad, A. K., Kadirvel, G., Mamgai, P., ... & Sarma, J. socio-economic empowerment and sustainable livelihood security of tribal farmers through technological intervention: an impact analysis.
27. Das, S., & Mishra, C. (2020). Orissa tribal empowerment & livelihood programme: Impact assessment.
28. Jain N.& Chandravanshi J.(2022). Role of Tribal Handicraft in the Development of the Rural Economy of Bastar, Chhattisgarh. *Arthavati: An International Journal*.,9, (1&2),95-145.
29. Sahu, V.K., Baral, S.K., & Singh, R. (2024). Financial Empowerment of Tribal Women: An Inquiry into Sustainable Economic Justice Initiatives and Pathways towards Inclusive Development. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 24(4), 182–194. DOI:10.9734/ajeba/2024/v24i41272
30. Jose, C. & Dhamodharan, M. (2025). MGNREGA and Tribal Empowerment: A Sociological Analysis of Economic and Social Transformation in Idukki District, Kerala. South Eastern European Journal of Public Health, XXVI(S1), 6069–6076. DOI:10.70135/seejph.

31. Tudu, R., Khatua, P., & Panda, L. (2025). Education and Economic Dimension of Tribal Women Empowerment in Mayurbhanj. Economic Sciences, 21(1), 145–152. DOI:10.69889/e2dmnh03 economic-sciences.com
32. Sodhi, D. (2024). Impact of MGNREGA on Economic Conditions of Tribal Community. JASRAE, 21(5), 74–79. DOI:10.29070/esh31k11 Ignited Minds.
33. Naik, R. & Dasaratharamaiah, K. (202x). Education and Socio Economic Development of Tribal Women: A Study. Shanlax International Journal of Economics. DOI:10.34293/economics.v7i4.608 shanlaxjournals.in.
34. Naveen, S., Parida, J.K., & Panda, I. (2023). Tribal Women Empowerment through Entrepreneurship: Evidence from Mayurbhanj District, Odisha. Frontiers in Sociology, 8:1158770. DOI:10.3389/fsoc.2023. 1158770 .
35. Tripathy, Sadasiba & Das, Sandhyarani. (2020). Impact of Crop Diversification on Tribal Farmers' Income: A Case Study from Eastern Ghats of India.
36. Dewangan, S.K., Sahu, K.R., Achari, K.V., & Soni, S. (2013). Socio Economic Empowerment of Tribal Women through Sericulture: A Study of Lailunga Block, Raigarh District, Chhattisgarh, India. International Journal of Business and Management, 6(12), 297–... DOI:10.5539/ijbm.v6n12p297.
37. Basu, A. & Bharti, P. (2016). Entrepreneurship Development among Tribals in India. Research Bulletin, 41(4), 78–91. DOI:10.33516/rb.v41i4.78-91p
38. Pillai, R. (2010). Eco development and Tribal Empowerment. MPRA Paper No. 22202. Munich Personal RePEc Archive
39. Lunavath, V. (20xx). Unveiling Economic Inequalities and Poverty among Tribal Communities: A Study in Telangana State. International Education and Research Journal (IERJ) IER Journal.
40. A "Photo Handbook of Kamar Tribe (PVTG)" (2020) by Anil Virulkar, providing visual and cultural documentation. repository.tribal.gov.in
41. A "Monograph Study of Customary Law in Kamar" (2022) by Jaimangal Patel, focusing on the tribe's legal and societal traditions. repository.tribal.gov.in

****